

माध्यमिक शिक्षा के विकास की वर्तमान स्थिति : चुनौतियाँ और अवसर

डॉ० अतुल कुमार श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Author Email: dr.atulsrivastava.07@gmail.com

सारांश— यह लेख भारत में एकीकृत माध्यमिक शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं पर केंद्रित है। लेख में बताया गया है कि 1950-51 में जहाँ केवल 7,416 माध्यमिक विद्यालय थे, वहीं 2021-22 तक यह संख्या बढ़कर 12,766 हो गई है। छात्र संख्या, विशेष रूप से लड़कियों की भागीदारी, में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी भारी गिरावट देखी जा रही है। पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता, अपर्याप्त संसाधन, शिक्षकों की कमी, छात्रों की अनुपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं का अभाव जैसे अनेक कारण माध्यमिक शिक्षा की कमजोरी के पीछे जिम्मेदार हैं।

सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं जैसेकृ

- कन्या शिक्षा योजना
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
- सुकन्या समृद्धि योजना
- छात्रवृत्ति योजनाएँ

इनका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और उपयोगी बनाना है।

लेख में यह भी सुझाया गया है कि गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।

शब्दकुंजी: एकीकृत माध्यमिक शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, सरकारी शिक्षा योजनाएँ, सामाजिक सहभागिता, प्रौद्योगिकी का उपयोग

I. प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा किसी भी देश के शैक्षिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छात्रों को उच्च शिक्षा और भविष्य के करियर के लिए तैयार करती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में कई चुनौतियाँ और अवसर हैं, जिनपर चर्चा करना आवश्यक है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वर्ष 1950-51 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की कुल संख्या 74,16 थी जो अब 2021-22 में बढ़कर 1 लाख 50 हजार से भी अधिक हो गई है। उस समय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत केवल 13.3 था माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की प्रतिशत संख्या वर्ष 2018-19 से लगातार बढ़ रही है 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक 12 करोड़ 29 लाख से अधिक छात्रों ने नामांकन कराया था जो 2021-22 की तुलना में 8 लाख 19 हजार से अधिक तक बढ़कर 37 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच चुका है। इन विद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या भी इस अवधि में 15 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 72 लाख हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रावधानों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। 11 वीं और 12 वीं कक्षा के स्तर पर देश में वर्तमान में लगभग 7 हजार स्कूलों में करीब 19 हजार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं फिर भी माध्यमिक शिक्षा में विशेष सुधार नहीं हो रहा है और दिन प्रतिदिन इसका स्तर गिरता जा रहा है।

यदि माध्यमिक शिक्षा की ओर दृष्टिपात करें तो माध्यमिक शिक्षा की काफी निराशाजनक तस्वीर सामने आती है माध्यमिक शिक्षा के असफलता के कई कारण हैं जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसके असफलता का सबसे प्रमुख

कारण है कि हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा आज भी विदेशी शिक्षा प्रणाली (मैकाले शिक्षा पद्धति) पर आधारित है तथा इसके साथ ही साथ इस शिक्षा के अवधि में बराबर परिवर्तन होते रहे हैं। देश में माध्यमिक शिक्षा में सैद्धांतिक अस्पष्टता का दोष पाया जाता है जिसके कारण यह असफल साबित हो रही है। इस के अलावा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, वित्तीय संसाधनों की कमी, अनुशासन हीनता, दोहरी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, शिक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रों की उदासीनता, अभिभावकों की उदासीनता, अध्यापकों में खामियां, प्रवेश की कमी, (कक्षा 10 तक पहुंचते –पहुंचते 61% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं) अति निम्न गुणवत्ता, शिक्षा व्यवस्था में असमानता, तथा भेदभाव जैसी अनेकानेक विद्रूपताओं ने माध्यमिक शिक्षा के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। माध्यमिक शिक्षा को इस स्थिति से उबारने के लिए सभी स्तरों से समन्वित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे इसे असफल होने से बचाया जा सके। 2

II. स्वतंत्रता काल में देश के माध्यमिक शिक्षा की प्रगति तालिका

क्र. सं.	विवरण	सन् 1950–1951	सन् 1998.–1999	सन् 2006–2007
1.	माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	7416	1.10 लाख	1,68,900
2	छात्रों की संख्या	15 लाख	272 लाख	3.94 करोड़
3	लड़कियों की संख्या	2 लाख 13.3%	101 लाख	
4	शिक्षकों की संख्या	1.27 लाख	15.42 लाख	
5	शिक्षक छात्र अनुपात	1:21	1:32	

वर्तमान में राज्य में कुल 12,766 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 548 राजकीय तथा 12,218 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें 67.64 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 63.34 लाख है। इनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 1,23,156 है।

इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के विकास में कई और चुनौतियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है जिसमें सर्वप्रथम गुणवत्ता की कमी माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है कई स्कूलों में पर्याप्त संसाधन नहीं है जैसे की योग्य शिक्षक पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं इसके साथ ही साथ पहुंच की भी कमी है। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की कमी भी एक बड़ी चुनौती है कई छात्र आर्थिक या सामाजिक कर्म से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता भी एक कारण बनकर सामने आती है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता भी एक चुनौती है पाठ्यक्रम को छात्रों की जरूरत और भविष्य के कैरियर के अनुसार अद्यतन करने की अत्यधिक आवश्यकता है इसके साथ शिक्षकों की कमी आधारभूत सुविधाओं की कमी माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी भी एक चुनौती है कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है जो छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी चुनौती है कई स्कूलों में शौचालय पेयजल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं है अक्सर माध्यमिक शिक्षा के विकास में कई अवसर भी हैं जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग नवाचारी शिक्षा पद्धति सामुदायिक भागीदारी सरकारी परियोजनाएं प्रौद्योगिकी का उपयोग माध्यमिक शिक्षा में एक बड़ा अवसर है ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है नवरी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग भी एक बड़ा अवसर है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा समस्या समाधान शिक्षा और सहयोगी शिक्षा जैसी पद्धतियों का उपयोग करके छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है सामुदायिक भागीदारी भी माध्यमिक शिक्षा में एक बड़ा अवसर है समुदाय के सदस्यों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करके छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है इस के साथ ही साथ सरकारी योजनाएं भी माध्यमिक शिक्षा में एक बड़ा अवसर है सरकार द्वारा चलाई जा रही माध्यमिक विद्यालयों के विकास हेतु संचालित योजनाओं पर अगर दृष्टिपात करें तो संख्या की दृष्टि से ये बहुत ही कम हैं। फिर भी उ०प्र० सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के विकास हेतु कुछ योजनाएं संचालित की गयी हैं जो इस प्रकार हैं—

- 1:- कन्या विद्याधन – पूर्व में उ०प्र० के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा कन्या विद्या धन योजना आरम्भ की गयी, जिसमें इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु बीस हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। लेकिन ये योजना अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, वर्तमान में उ०प्र० की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने इस योजना को बन्द कर दिया तथा एक नयी योजना की शुरुआत की।
- 2:- राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना-सरकार ने प्रति वर्ष 100000 छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की जिस के अन्तर्गत कक्षा 9-12 में अध्ययन के लिए प्रत्येक छात्र को 6000 रुपये प्रति वर्ष (500 रुपये प्रतिमाह) दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
- 3:- बालिका प्रोत्साहन योजना भारत सरकार ने जून 2008 से माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं प्रोत्साहन नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की। इस योजना के अनुसार एक निश्चित जमा राशि के रूप में पात्र बालिका के नाम पर 3000 रुपये की राशि जमा की जायेगी और वह बालिका 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित वह राशि प्राप्त करने की हकदार होगी।
- 4:- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन 2008-09 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और इसकी वैश्विक पहुँच के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक व्यापक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की गई।
- 5:- नयी केन्द्र प्रायोजित योजना 2008-09 से इस योजना के प्रथम चरण में देश के प्रत्येक ब्लाक में एक उच्चगुणवत्ता मॉडल विद्यालय स्थापित किए जाने का प्राविधान है जो उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में शिक्षा प्रदान करेगा।
- 6:- सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना-उ०प्र० सरकार द्वारा 4 फरवरी 2009 को वर्तमान 'मुख्यमंत्री सुश्री मायावती' ने लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से "सावित्रीबाईफूले बालिका शिक्षा मदद योजना" प्रारम्भ की। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा अपने जन्म दिन 15 जनवरी 2009 को की।

III. निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के विकास में कई चुनौतियाँ और अवसर हैं। गुणवत्ता की कमी, पहुँच की कमी, और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें नवाचारी शिक्षा पद्धतियों, औद्योगिकी के उपयोग, और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करना होगा। यदि हम इस अवसरों का लाभ उठाते हैं तो हम माध्यमिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी और सुलभ बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1:- कुरुक्षेत्र पत्रिका, सितंबर 2006 वर्ष 52 संपादक कुरुक्षेत्र, कमरा नम्बर 665/661] गेट नम्बर 5] निर्मन भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली पृष्ठ 14
- 2:- भारत पत्रिका, 2001] प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 91 (आंकड़ा 2001 की जनगणना के अनुसार)
- 3:- स्रोत- क्रम संख्या 3]4] 5 और 6 योजना पत्रिका सितंबर 2009 पृष्ठ संख्या 21